रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-69/2025/1895/22-2-2023-17(767)/2023
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी अनवरी (बन्दी संख्या-2572/2022) पत्नी श्री मिजाज, निवासी-घोड़े वाली गली सोतीगंज, थाना-सदर बाजार, जनपद-मेरठ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-329/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमैण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-02, मेरठ के आदेश दिनांक 22.12.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2023 तक 13 वर्ष, 00 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की 74 वर्ष की आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण, महिला बन्दी की वृद्धावस्था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2025/1895(1)/22-2-2023-17(767)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in